नईदुनिया

एचडीएफसी बैंक को क्लीन चिट के बाद चेयरमैन की तलाश तेज

नई दिल्ली

निजी क्षेत्र के प्रमुख ऋणदाता एचडीएफसी बैंक को पूर्व अंशकालिक चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती द्वारा लगाए गए आरोपों की कानूनी समीक्षा में हाल ही में क्लीन चिट मिलने के बाद, बैंक प्रबंधन ने अपनी शीर्ष प्राथमिकता तय कर ली है। बैंक अब जल्द से जल्द एक नियमित चेयरमैन की नियुक्ति करेगा।

सीईओ शशिधर जगदीशन के कार्यकाल विस्तार पर भी होगा विचार

यह कदम प्रबंध निदेशक और सीईओ शशिधर जगदीशन के कार्यकाल विस्तार पर विचार करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, नए चेयरमैन की नियुक्ति अगले दो हफ्तों में होने की संभावना है, जिसके बाद जुलाई के अंत तक सीईओ के भविष्य पर निर्णय लिया जा सकता है।

बैंक बोर्ड के लिए नियमित चेयरमैन की नियुक्ति सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि सीईओ के कार्यकाल को आगे बढ़ाने के लिए नए चेयरमैन की राय अहम होगी। अतनु चक्रवर्ती ने अपने इस्तीफे की वजह बताते हुए कहा था कि बैंक के अंदर कुछ घटनाएं और तौर-तरीके उनके निजी मूल्यों और नैतिकता के अनुरूप नहीं थे।

उनके इस्तीफे के बाद से, अनुभवी बैंकर और स्वतंत्र निदेशक केकी मिस्त्री ने अंतरिम अंशकालिक चेयरमैन का पद संभाला है, जिन्हें हाल ही में 18 सितंबर तक या किसी नियमित चेयरमैन की नियुक्ति तक, जो भी पहले हो, तीन महीने का सेवा विस्तार दिया गया है। एचडीएफसी बैंक बीते कुछ समय से नियमित चेयरमैन की तलाश कर रहा है और उसने इसके लिए एक टैलेंट सर्च फर्म को भी नियुक्त किया था।

समिति ने कई नामों पर चर्चा की थी और कुछ उम्मीदवारों को छांटा भी था, लेकिन विभिन्न कारणों से अभी तक किसी का नाम तय नहीं हो पाया है। वर्तमान प्रबंध निदेशक और सीईओ शशिधर जगदीशन का मौजूदा कार्यकाल अक्टूबर में समाप्त हो रहा है। बैंक ने इस पूरी प्रक्रिया की जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को समय-समय पर दी है, जिससे किसी भी तरह की नियामकीय रुकावटों की आशंका नहीं है। यदि चेयरमैन की नियुक्ति जुलाई मध्य तक हो जाती है, तो सीईओ के कार्यकाल विस्तार पर भी उसी महीने फैसला होने की उम्मीद है। जगदीशन को 2020 में तीन साल के लिए नियुक्त किया गया था और 2023 में उनके कार्यकाल को तीन साल और बढ़ाया गया था।

न्यूज ब्रीफ

आरईसी के पीएफसी में विलय की योजना को दोनों कंपनियों के निदेशक मंडल की मंजूरी

नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) लिमिटेड के निदेशक मंडलों ने आरईसी के पीएफसी में विलय की योजना को मंजूरी दे दी है। आरईसी का पीएफसी में विलय होने से एक ऐसी वित्तीय कंपनी बनेगी, जिसका कुल कर्ज खाता 11 लाख करोड़ रुपये से अधिक का होगा। शेयर बाजार को देर रात दोनों कंपनियों ने इस विलय की जानकारी दी। सोमवार को कारोबार के दौरान दिन में करीब आरईसी के शेयर 0.37 फीसदी यानी 1.35 रुपये चढ़कर 366 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे, जबकि पीएफसी के शेयर 1.56 फीसदी यानी कि करीब 6.75 रुपये टूटकर 425.90 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे थे। आरईसी के पीएफसी में विलय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230-232 और अन्य लागू प्रावधानों के तहत किया जाएगा, जिसमें संबंधित शेयरधारकों तथा कर्जदाताओं को भी शामिल किया गया है। ये विलय कई शर्तों पर निर्भर है। इनमें दोनों कंपनियों के शेयरधारकों और कर्जदाताओं की मंजूरी और सभी संबंधित नियामकीय तथा सरकारी प्राधिकरणों की मंजूरी शामिल है। दोनों कंपनियों के संयुक्त बयान के अनुसार विलय के बाद बनी कंपनी का कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत सरकारी कंपनी का दर्जा बनाए रखना और भारत सरकार का विलय के बाद बनी कंपनी में (सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से) ज्यादातर मतदान अधिकार और नियंत्रण बनाए रखना भी जरूरी है।

इक्विटी म्युचुअल फंडों में एसआईपी की हिस्सेदारी 40 फीसदी के पार, खुदरा निवेशकों की बढ़ती समझदारी और भागीदारी का संकेत

नई दिल्ली। बाजार में उतार-चढ़ाव और कोविड-19 महामारी के बाद की तेजी में आई सुस्ती के बावजूद, सक्रिय इक्विटी म्यूचुअल फंडों में सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। मई 2026 के अंत तक, एसआईपी से जुड़ी परिसंपत्तियों की हिस्सेदारी कुल प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियों (एयूएम) का 40.4 प्रतिशत हो गई है, जो निवेशकों के भरोसे और अनुशासित निवेश का प्रमाण है। यह जनवरी में पहली बार 40% का आंकड़ा पार करने के बाद से लगातार बढ़ता रुझान है। उद्योग के आंकड़ों के अनुसार, निवेशकों द्वारा किस्तों में लगातार निवेश जारी रखने से सक्रिय इक्विटी म्युचुअल फंडों में एसआईपी की हिस्सेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मई 2026 में यह आंकड़ा 40.4 प्रतिशत तक पहुंच गया, जबकि दिसंबर 2025 में यह 40 प्रतिशत और एक वर्ष पूर्व 38.8 प्रतिशत था।

भारत का रिटायरमेंट रेडीनेस स्कोर केवल 48, भविष्य की वित्तीय सुरक्षा पर बढ़ी चिंता

भोपाल। भारत का राष्ट्रीय रिटायरमेंट रेडीनेस स्कोर 100 में से केवल 48 है, जो भविष्य की वित्तीय तैयारी की कमजोर स्थिति को दर्शाता है। एक्सिस मैक्स लाइफ इंडिया रिटायरमेंट इंडेक्स स्टडी (आइरिस 5.0) के अनुसार, लंबी होती औसत आयु के बावजूद अधिकांश लोग रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त बचत नहीं कर पा रहे हैं।

सर्वे में पाया गया कि 86 प्रतिशत एम्प्टी नेस्टर्स को अपनी वित्तीय जरूरतों का अनुमान है, लेकिन केवल 33 प्रतिशत को भरोसा है कि उनकी बचत रिटायरमेंट के बाद 10 वर्ष से अधिक चलेगी। वहीं, सैंडविच जनरेशन के केवल 38 प्रतिशत लोगों को अपने रिटायरमेंट फंड पर विश्वास है।

अध्ययन में यह भी सामने आया कि 77 प्रतिशत शहरी भारतीय 1 करोड़ रुपये को रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त मानते हैं, जबकि महंगाई और बढ़ते चिकित्सा खर्च इस राशि की वास्तविक क्रय शक्ति को काफी कम कर सकते हैं। विशेषज्ञों ने समय रहते दीर्घकालिक निवेश, म्यूचुअल फंड, एसआईपी और नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) जैसे विकल्प अपनाकर वित्तीय सुरक्षा मजबूत करने की सलाह दी है।

गिफ्ट सिटी से सीमा-पार भुगतान सेवाओं को नई उड़ान

भारतीय कंपनियां सीमा-पार भुगतान सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए अपना रही हैं एक नई रणनीति

नई दिल्ली

फिनटेक कंपनियां आईएफएससीए के पीएसपी लाइसेंस से घरेलू नियामकीय ढांचे से बाहर निकलकर पूंजी बाजार और बहु-मुद्रा भुगतान जैसे वैश्विक अवसरों का लाभ उठाएंगी। डिसेंट्रो, स्काइडो और एक्सफ्लो को मंजूरी। भारतीय कंपनियां सीमा-पार भुगतान सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए एक नई रणनीति अपना रही हैं। इसका उद्देश्य घरेलू नियामक ढांचे की सीमाओं से बाहर निकलकर अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) के भुगतान सेवा प्रदाता (पीएसपी) लाइसेंस के माध्यम से नए कारोबारी अवसरों का लाभ उठाना है। यह कदम कंपनियों को पूंजी बाजार से जुड़े लेनदेन, ट्रेजरी सुविधाओं और कई मुद्राओं में भुगतान समाधान उपलब्ध कराने में सक्षम बनाएगा, जो भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के मौजूदा पेमेंट एग्रीगेटर-क्रास बार्डर (पीए-सीबी) नियमों के तहत संभव नहीं थे। इस पहल के तहत, स्काइडो और एक्सफ्लो जैसी फिनटेक कंपनियों को आईएफएससीए से पीएसपी लाइसेंस के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है, जबकि डिसेंट्रो ने पूर्ण लाइसेंस हासिल कर लिया है। ये कंपनियां इस वर्ष अपना परिचालन शुरू करने के लिए बैंकों के साथ साझेदारी कर रही हैं। डिसेंट्रो के एक अधिकारी ने बताया, गिफ्ट सिटी में ट्रेड फाइनेंस और ट्रेजरी जैसी सेवाओं की बढ़ती मांग के साथ, हम 2027 के अंत तक पीएसपी लाइसेंस कारोबार से लगभग 10 लाख डालर का राजस्व हासिल करने का लक्ष्य रख रहे हैं। गिफ्ट सिटी को विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं के लिए विकसित किया गया है, और इसका पीएसपी लाइसेंस खाता जारी करने, एस्क्रो सेवाओं, सीमा-पार धन हस्तांतरण और व्यापारियों को जोड़ने जैसी पांच प्रमुख गतिविधियों की अनुमति देता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार वित्तपोषण सेवा मंच (आईटीएफएस) के संचालक भी भारत के ई-नैच की तरह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले भुगतान ढांचे की मांग कर रहे हैं, जिससे पीएसपी कंपनियों के लिए नए कारोबारी अवसर पैदा हो रहे हैं।

कुपोषण से जंग, मिशन सेहत से बदलेगी कृषि-स्वास्थ्य रणनीति , पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य उत्पादन और रोगों की रोकथाम पर जोर

नई दिल्ली। देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद, भारत ने अब अपना ध्यान पोषण सुरक्षा पर केंद्रित किया है। इस दिशा में, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और भारतीय चिकित्सा शोध परिषद (आईसीएमआर) ने मिशन सेहत लान्च किया है। इसका लक्ष्य कृषि और स्वास्थ्य मंत्रालयों के बीच तालमेल बिठाकर पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य उत्पादन और रोगों की रोकथाम पर जोर देना है। यह पहल ऐसे समय में आई है जब अध्ययनों से पता चला है कि आधुनिक उच्च उपज वाली फसलों में कैल्शियम, आयरन और फास्फोरस जैसे आवश्यक पोषक तत्व अपनी पारंपरिक किस्मों की तुलना में 38 फीसदी तक कम होते हैं। यही कारण है कि पर्याप्त अनाज के बावजूद देश में बड़े पैमाने पर कुपोषण और पोषण की कमी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6 (2023-24) के अनुसार, देश की 19.7 फीसदी आबादी कम वजन वाली है, जबकि 27.3 फीसदी पुरुष और 30.7 फीसदी महिलाएं मोटापे का शिकार हैं। पांच साल से कम उम्र के 31.8 फीसदी बच्चे भी कम वजन के हैं। इन चिंताजनक आंकड़ों के मद्देनजर, कृषि मंत्रालय जो पहले केवल कैलोरी आवश्यकताओं पर केंद्रित था, और स्वास्थ्य मंत्रालय जो मुख्य रूप से बीमारियों के इलाज पर ध्यान देता था, अब मिशन सेहत के तहत पोषण सुरक्षा और रोगों की रोकथाम के लिए मिलकर काम करेंगे।

केंद्र ने कारोबार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया

नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने व्यापार करने में आसानी (ईओडीबी) को बढ़ावा देने के लिए सुधार सूचना तंत्र की शुरुआत की है। इसे जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम के जरिए लागू किया गया है, जो व्यवसायों को बिना दंड के प्रक्रियात्मक कमियों को सुधारने का मौका देता है।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मुताबिक इस नई व्यवस्था के तहत अगर कोई कारोबार पहली बार प्रक्रिया या नियमों का पालन करने में कोई तय चूक करता है, तो उसे दंडात्मक कार्रवाई शुरू होने से पहले उस कमी को ठीक करने का मौका दिया जाएगा। इस सुधार का मकसद ईज आफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) को बढ़ावा देना है। यह सुधार ईओडीबी को बढ़ावा देता है। यह स्वेच्छा से नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करता है, अनावश्यक कानूनी विवादों को कम करता है और भरोसे पर आधारित रेगुलेटरी सिस्टम को सपोर्ट करता है। इसके साथ ही उपभोक्ताओं की मज़बूत सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है।

मंत्रालय ने कहा कि इसे जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया है, जो व्यवसायों को बिना दंड के प्रक्रियात्मक कमियों को सुधारने का मौका देता है। इसके लिए स्वेच्छा से नियमों का पालन करने को प्रोत्साहित किया जाएगा, बेवजह के कानूनी विवाद कम किए जाएंगे और भरोसे पर आधारित रेगुलेटरी सिस्टम को सपोर्ट किया जाएगा, साथ ही उपभोक्ताओं की सुरक्षा भी मजबूत बनी रहेगी।

सुधार नोटिस सिस्टम पहली बार होने वाली कुछ खास प्रक्रियात्मक और रेगुलेटरी कमियों पर लागू होता है, जिसमें रजिस्ट्रेशन की जरूरतें, डाक्यूमेंटेशन और रिकार्ड रखना, माडल मंजूरी, वजन और माप का निर्माण, बिक्री और मरम्मत, वजन और माप का आयात, लेन-देन और पैक्ड सामान, कानूनी जानकारी और रिटर्न देना आदि हैं।

आर्थिक अनिश्चितता का असर, 7 शहरों में आवासीय बिक्री 6 फीसदी घटी

नई दिल्ली। आर्थिक अनिश्चितता और लगातार बढ़ती कीमतों के कारण देश के सात प्रमुख शहरों में अप्रैल-जून तिमाही के दौरान आवासीय बिक्री छह प्रतिशत घटकर 90,715 इकाई रह गई है। रियल एस्टेट सलाहकार कंपनी एनाराक द्वारा सोमवार को जारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली। रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई, दिल्ली-एनसीआर, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता में पिछले साल की समान अवधि में 96,285 आवासीय इकाइयां बिकी थीं। एनाराक ने इस तिमाही में मकानों की औसत कीमत में सात प्रतिशत की वृद्धि भी दर्ज की है। वहीं, दिल्ली-एनसीआर में यह वृद्धि सर्वाधिक 13 प्रतिशत रही। एनाराक के चेयरमैन अनुज पुरी ने कहा कि पश्चिमी एशिया युद्ध और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कृत्रिम मेधा से जुड़ी अनिश्चितताओं के चलते कई खरीदार फिलहाल खरीदारी का फैसला टाल रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब आवासीय मांग मुख्य रूप से प्रीमियम आवास और बुनियादी ढांचा विकास वाले क्षेत्रों तक सीमित हो गई है। हालांकि, इस तिमाही में नई आवासीय परियोजनाओं की पेशकश सात प्रतिशत बढ़कर 1,06,000 इकाई हो गई, जो पिछले वर्ष 98,625 इकाई थी। यह आंकड़ा हाल ही में सूचीबद्ध प्रापइक्विटी की रिपोर्ट के विपरीत है, जिसमें 19 प्रतिशत बिक्री वृद्धि का दावा किया गया था।

सर्राफा बाजार में मामूली गिरावट, सोना और चांदी की फीकी पड़ी चमक

नई दिल्ली

घरेलू सर्राफा बाजार में शुरुआती कारोबार के दौरान सांकेतिक कमजोरी नजर आ रही है। भाव में आई गिरावट के कारण देश के ज्यादातर सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना 1,43,940 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,45,850 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना 1,31,940 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,33,690 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। चांदी के भाव में भी मामूली गिरावट होने के कारण ये चमकीली धातु दिल्ली सर्राफा बाजार में 2,39,900 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बिक रही है।

दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,44,090 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,32,090 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,43,940 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,31,940 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 1,43,990 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,31,990 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है।

इन प्रमुख शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना 1,45,850 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 1,33,690 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। इसी तरह कोलकाता में 24 कैरेट सोना 1,43,940 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,31,940 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। भोपाल में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,43,990 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,31,990 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

जयपुर में 24 कैरेट सोना 1,44,090 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,32,090 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। पटना में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,43,990 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,31,990 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। लखनऊ के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना 1,44,090 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर और 22 कैरेट सोना 1,32,090 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। देश के अन्य राज्यों की तरह कर्नाटक, तेलंगाना और ओडिशा के सर्राफा बाजार में भी सोने के भाव में मामूली कमजोरी दर्ज की गई है। इन तीनों राज्यों की राजधानियों बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में 24 कैरेट सोना 1,43,940 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह इन तीनों शहरों के सर्राफा बाजारों में 22 कैरेट सोना 1,31,940 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

ग्लोबल मार्केट से कमजोरी के संकेत, एशिया में मिला-जुला कारोबार

नई दिल्ली

पश्चिम एशिया में लगातार बदल रहे माहौल के बीच ग्लोबल मार्केट से कमजोरी के संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकी बाजार पिछले सत्र के दौरान कमजोरी के साथ बंद हुए, जबकि डाउ जान्स फ्यूचर्स फिलहाल मामूली तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। इसी तरह यूरोपीय बाजार में भी पिछले सत्र के दौरान बिकवाली का दबाव बना रहा। वहीं एशियाई बाजार में मिला-जुला कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है।

अमेरिका और ईरान ने वीकेंड पर एक दूसरे पर नए हमले करने और सीजफायर तोड़ने के आरोप लगाए। हालांकि अब एक बार फिर खबर आ रही है कि दोनों देश हमले रोकने की बात पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों के बीच जारी खींचतान के कारण पिछले सत्र के दौरान अमेरिकी बाजार में निवेशक लगातार सतर्क मुद्रा में कारोबार करते रहे। निवेशकों की सतर्कता की वजह से वाल स्ट्रीट के सूचकांक पिछले सत्र के दौरान लाल निशान में बंद हुए।

डाउ जान्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.09 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 51,876.11 अंक के स्तर पर आ गया। इसी तरह एस एंड पी 500 इंडेक्स ने 0.05 प्रतिशत की गिरावट के साथ 7,354.02 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। इसके अलावा नैस्डेक 0.24 प्रतिशत टूट कर 25,297.62 अंक के स्तर पर बंद हुआ। वहीं डाउ जान्स फ्यूचर्स फिलहाल 0.09 प्रतिशत की मजबूती के साथ 51,923.09 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा है।

यूरोपीय बाजार भी पिछले सत्र के दौरान कमजोरी के साथ बंद हुए।

एफटीएसई इंडेक्स 0.21 प्रतिशत की गिरावट के साथ 10,508.02 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह सीएसी इंडेक्स ने 0.56 प्रतिशत टूट कर 8,384.87 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। इसके अलावा डीएएक्स इंडेक्स 323.61 अंक यानी 1.31 प्रतिशत फिसल कर 24,671.22 अंक के स्तर पर बंद हुआ।

एशियाई बाजार में मिला-जुला कारोबार हो रहा है। एशिया के नौ बाजार में से छह के सूचकांक मजबूती के साथ हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, जबकि तीन सूचकांक गिरावट के साथ लाल निशान में बने हुए हैं। निक्केई इंडेक्स 540.88 अंक यानी 0.78 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 68,820 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह जकार्ता कंपोजिट इंडेक्स 0.63 प्रतिशत लुढ़क कर 5,859.17 अंक के स्तर पर पहुंचा हुआ है। कोस्पी इंडेक्स में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। फिलहाल यह सूचकांक 190.89 अंक यानी 2.20 प्रतिशत टूट कर 8,220.32 अंक के स्तर पर आ गया है।

दूसरी ओर, गिफ्ट निफ्टी 0.03 प्रतिशत की सांकेतिक बढ़त के साथ 24,104 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.09 प्रतिशत की मामूली तेजी के साथ 5,196.58 अंक के स्तर पर पहुंचा हुआ है। हैंग सेंग इंडेक्स ने बड़ी छलांग लगाई है। फिलहाल यह सूचकांक 472.14 अंक यानी 2.08 प्रतिशत उछल कर 23,144 अंक के स्तर पर आ गया है।

इसी तरह सेट कंपोजिट इंडेक्स में भी अच्छी मजबूती दिख रही है। फिलहाल यह सूचकांक 1.45 प्रतिशत की उछाल के साथ 1,564.66 अंक के स्तर पर पहुंचा हुआ है। इसके अलावा ताइवान वेटेड इंडेक्स 494.09 अंक यानी 1.11 प्रतिशत की तेजी के साथ 45,065.85 के स्तर पर और शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.17 प्रतिशत की बढ़त के साथ 4,034.08 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहे हैं।